17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PROPOSAL TO DECLARE WHOLE OF RAJASTHAN AS FAMINE AFFECTED

MR. CHAIRMAN: Now we take up the Half-an-hour discussion by Mr. M. C. Daga.

Mr. Daga.

श्री मूल चन्द डागा (पाली): सभापति महोदय, राजस्थान की जो चिन्ताजनक तस्वीर है, वह मैं माननीय शिण्डे साहब के लिये उन के ही शब्दो में याद दिलाते हुए कहना चाहता हू। उन्होंने कहा था —

> "The people of all the States are our brothers and sisters and we do not discriminate between State and State."

दूसरी बात आप ने यह कही थी —

> "We are constantly watching the situation and keeping ourselves in close touch with the State Government."

आप के जो ये आश्वाशन भरे हुए और सच्चे दिल से निकले हुए वाक्य हैं, यदि उनको याद दिलाते हुए राजस्थान की 1 करोड़ 49 लाख जनता की याद दिलाना चाहता हूं, जो अकाल से प्रभावित है और जिस की प्रदेश की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि जिस पर आज 824 करोड़ रुपये का कर्जा है, यानी हर राजस्थानी पर आज 47 रूपये 80 पैसे का कर्जा है।...

श्री शशी भूषण (दक्षिण दिल्ली): केन्द्र का है या अन्तर्राष्ट्रीय है।

श्री मूल चन्द डागा: केन्द्र का है और 824 करोड़ रूपये का कर्जा है। जिस की आर्थिक हालत बिगड़ चुकी है और चेयरमैन साहब, केन्द्र सरकार ने यह बैन भी लगा दिया है कि हम 10 करोड़ रुपये से ज्यादा रिजर्व बैंक सें ओवर-ड्राफ्ट भी नहीं ले सकते। इस लिये आज हम आप की सेवा में, आप के दिल में हमारे लिये जो हमदर्दी है, उस को ध्यान में रख कर आये हैं।

शिण्डे साहब, अगर आप को समय मिल जाय तो अपनी पहली, दूसरी और तीसरी स्टडी टीमों के अलावा, आप खुद वहां के कोने कोने में जा कर वहां के गरीबों की हालत को देखें, सभापति जी, आप खुद भी वहां चलें तो आप को मालूम हो जायगा कि आज वहां पर क्या हालत है। हम इस बात को जलन से नहीं कहते कि महाराष्ट्र को 70 करोड़ रुपया मिल गया, हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, राजस्थान को सिर्फ सात करोड़ रुपया ही मिला, यह भी तकलीफ़ नहीं है, आप के यहां आज 30 लाख आदमी काम करते हैं, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है, चूकि यह नैशनल कलैमिटी है, यह राष्ट्रीयता का प्रश्न है, यह मानवता का प्रश्न है, इस लिये अगर महाराष्ट्र को 70 करोड़ रुपये मिले, तो मैं यही कहूंगा कि आप ने बड़ा भारी हिम्मत का कदम उठाया है, आप उसके लिये बधाई के पात्र हैं, पचास करोड़ रुपया आप को बैंक से मिल जायगा, ढाई अरब का आप का टारगेट है, लेकिन हमारे राजस्थान में क्या होगा? आप के लिये राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों बराबर है। आप ने वहां 70 करोड़ रुपया दिया, यहां सात करोड़ ही दिया, वहा तीस लाख आदमी काम करते है यहां सिर्फ 5 लाख आदमी काम करते हैं, तो आप बतलाये कि राजस्तान के लोग कब तक इस तरह से जिन्दगी बितायेंगे, कब तक ऐसे चलेगा।

हम लोग आज बड़ी तकलीफ और कठिनाइयों में हैं। आर्थिक हालत खराब है, बरसात नहीं है, आकाश से बादल नहीं बरसे है, उनकी मेहरबानी नही हुई है, लेकिन आप भी नहीं बरस रहे हैं—कैसे काम

[श्री मूलचन्द डागा]

चलेगा ? सब से बड़ी बात तो यह है कि हम को काम नहीं देते हैं। अनाज को ले लीजिये– आप ने हम को क्या दिया है ? यदि आप 8 किलोग्राम आदमी को और 4 किलोग्राम बच्चे को देना चाहते हैं तो राजस्थान के लिये जिस की जनसंख्या 2 करोड़ 57 लाख है उसको 87 हजार 800 टन अनाज चाहिये, जिस में शहरी जनता के लिये हम को 30 हजार 832 टन अनाज चाहिये यानी हम को पूरा अनाज एक महीने के लिये 1 लाख 18 हजार 432 टन चाहिये। लेकिन आप ने हमें क्या दिया है ? मैं आप के सामने आंकडे रखना चाहता हू— जिससे आप को मालूम हो सके कि हम क्या माग रहे है और आप क्या हमे द रहे है। राजस्थान मे एफ०सी० आई० का अनाज पड़ा था, उस को भी आपने महाराष्ट्र भेज दिया, जिस का नतीजा यह हुआ है कि आज दो किलो अनाज भी गावों को नही मिलता है। कहा गया कि कार्नग्रेन मिल जायगा, वह भी उपलब्ध नही है। मैं आप का बतलाना चाहता हू कि मार्च, 1973 मे हमको 84 हजार टन अनाज की आवश्यकता है, लेकिन आपने हमको उस का आधा अनाज भी नही दिया फरवरी के कोटे को देख लीजिये जो कुछ हमारे यहा था वह तो आपने बाहर भेज दिया 1-10-72 को हमारे यहा 2 लाख 25 हजार 738 टन अनाज था 15–1–73 को घट कर 1 लाख 65 हजार टन रह गया 31–1–73 को घट कर 1 लाख 44 हजार टन रह गया सारा राजस्थान अनाज के लिये तड़प रहा है हम अपना कोटा मागते हैं लेकिन आप दे नहीं सकते, दूसरे प्रान्तों को भेज रहे है– किस तरह से ऐसा चलेगा। हम को आप क्या देना चाहते है

पानी के वास्ते आपको व्यवस्था नही हो सकी है। हम ने 100 ट्रक्टर्स मागे थे और कहा था कि डिफेन्स डिपार्टमेन्ट से उधार दिला दिला दीजिये ताकि हम लोगो को पानी पहुचा सकें —वह व्यवस्था भी आप ने नहर की। मै तुलना की दृष्टि से नही कह रहा हू —महाराष्ट्र मे अकाल है, यह ठीक है, आप वहा के लिये जो काम कर रहे हैं, वह भी ठीक हैं, लेकिन मैं आप की सुविधा की दृष्टि से कुछ आकडे रखना चाहता हू—महाराष्ट्र मे जिस प्रकार बूढ़ो, अन्धो और गरीबो का, लगभग 40 हजार को काम दे रहे हैं, राजस्थान मे केवल पाच हजार लोगो को वह पैसा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के लिये आप ने इन एडीशन 10 करोड़ रुपया शार्ट टर्म लोन के रूप मे मन्जूर किया है जो एग्रीकल्चरिस्ट्स को लोन की शक्ल मे दिया जायगा, 24 करोड़ रुपया आपने एमर्जेन्सी प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत दिया है, जब कि राजस्थान को केवल 3 करोड़ रुपया दिया है। आप किसी भी आकडे का ले लीजिये—तकावी लोन के लिये आपने पैसा दिया है।

सभापति महादय, राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। बम्बई के लोगो ने भी पैसा इकट्ठा किया है, वे लोग इस काम मे अलग से मदद कर रहे हैं, आप ने जो पहली स्टडी टीम राजस्थान मे भेजी, वह जुलाई 1972 मे गई आप ने 2 करोड़ 45 लाख रुपया दिया। दूसरी टीम गई, उसमे 4 करोड़ 81 लाख रुपया दिया, तीसरी स्टडी टीम का आज तक पता नही है। मैं आप से पूछना चाहता हू कि क्या स्टडी टीमो के भरोसे रह कर राजस्थान को भूखा मारना चाहते है। हम राजस्थान मे लोगो से जाकर क्या कहे ? हम राजस्थान के एम० पीज० लोगो से जा कर यही कहते है—श्रीमती इन्दिरा गाधी की सरकार मे शिन्डे साहब और चव्हाण साहब बैठे हुए है, राजस्थान का कोई भी आदमी भूख से मरने नही दिया जायगा।

अब राजस्थान का कोई आदमी भूख से मरने नही दिया जावेगा। लेकिन वास्तविकता तब जमीन पर आती है जब हम लोक घेराव मे फँसते हैं। तब हम लोगो को क्या उत्तर दे? हमने कहा था कि आप

हमने कहा था स्टडी टीम को कि 15 परसेन्ट मैटीरियल और काम्पोनेन्ट्स मे सडक कैसे बन सकती है, कम से कम 35 परसेन्ट या 45 परसेन्ट देंगे तभी सडक बन सकती है। लेकिन कहते हैं कि नही, हम तो 15 परसेन्ट ही देंगे मैटीरियल के लिए। तो फिर सडक किस प्रकार से बन सकती है ? अगर हम ऐसी सडक बनायेंगे तो फिर आप कहेंगे कि राजस्थान ने पैसा बर्बाद कर दिया। आपकी स्टडी टीम चाहती क्या है? क्या कभी आपने स्टडी टीम मे एम० पीज को भी बुलाया है ? क्या कभी आप हमारे साथ भी घूमें है। शिन्दे साहब, आप मेहरबानी करके एम० पीज के साथ एक दफा टूर कीजिए। अमृत नाहाटा जी यहा पर हैं, मैं नही कहता कि महाराष्ट्र मे चार रेलगाडिया न चले, भगवान करे वहा पर 11 और चले लेकिन अहमदाबाद की लाइन आप ब्राडगेज कर दीजिए। दिल्ली से कोटा की लाइन कर दीजिए। हमने चार सजेस्चन्स दिये है लेकिन सब बेकार है। (व्यवधान) अजमेर मे कोटा कर दीजिए कहीं न कही तो करिए। राज बहादुर जी है, हमने नेशनल हाई वे के लिए कहा लेकिन रत्नागिरि से नेशनल हाई वे शुरू कर दिया। हमने कहा नेशनल हाई वे बयावर मे लेकर ऊदयपुर का हिस्सा दे दीजिए। किशनगढ के पास बाई पास दे दीजिए। भीलवाडा के पास दे दीजिए नेशनल हाई वे, लेकिन न सडकें बनती हैं और न कुछ और होता है। सबसे दुःख की बात यह है कि मजदूरो को दो तीन रुपए भी नही मिलते हैं। जिन लोगो ने कभी जिन्दगी भर मिट्टी खोदी नही वह मजदूरी करने पर मजबूर हैं और उनसे कहते है कि इतना काम करना पडेगा तब इतना पैसा मिलेगा। उनको 70 या 80 पैसे मिलते है। उनसे कहा जाता है कि तुमने इतना ही काम किया है। जिन्होने जिन्दगी भर जमीन नही खोदी उनको पी डब्लू डी के मापदण्ड बताते हैं। एक तरफ न अनाज का वितरण है और न फेयर प्राइस शाप्स हैं। महाराष्ट्र में 23 हजार हैं तो हमारे यहा सिर्फ 4600। कहते हैं क्या करे धान ही नही है। पानी की व्यवस्था भी नही है। न रेलगाड़ी की लाइन ठीक होती है, न पक्की सडक की व्यवस्था है और न इरीगेशन के लिए पैसा है। सभापति जी, मैं निवेदन करुगा कि आप भी शिन्दे साहब पर अपना असर डालकर राजस्थान की यात्रा का प्रबन्ध करायें। अप्रैल मई के महीने मे लोग भूख से तड़पेंगे और प्यास मे मरेंगें और शिन्दे साहब और चव्हाण साहब को याद करेंगे। राजस्थान की स्टडी टीम कब रिपोर्ट देगी ? हम लोग भी स्टडी करने वाले हैं क्योकि हम घर घर जाते हैं इसलिए आप हम पर विश्वास करें। आपकी मीठी आवाज और आप की आश्वासन भरी बाते सतोष नही दे सकती है। सतोष देने के लिए खजाने से पैसा देना चाहिए और आप काम को खुद जाकर देखें वरना कही राजस्थान के दो करोड 40 लाख लोग यह न कहे कि गवर्नमेंट उनके प्रति सतर्क नही थी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जोधपुर का जो इलाका है वहा पर [illegible] नही है। काम बहुत कम है। वहा के लोग बहुत परेशानी मे आ गए है और दूसरी तरफ एम0 पीज की बदनामी अखबारो में हो रही है। इसलिए सभी जगह पर काम की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री बशेश्वर नाथ भार्गव (अजमेर) सभापति महोदय, राजस्थान की भयकर अकाल की परिस्थिति से मैं समझता हू मत्री महोदय स्वय भी बहुत अच्छी तरह मे परिचित है। राजस्थान मे लगातार 1963 से किसी न किसी इलाके मे भयकर अकाल की परिस्थिति रहती है और आज राज्य सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है, उसकी आर्थिक दशा जो है वह इतनी दयनीय है कि वह पर्याप्त मात्रा मे वहा के अकाल ग्रस्त क्षेत्रो मे रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नही कर पा रही है केन्द्रीय सरकार एक और तो कहती है कि हमारी पूर्ण सहानुभूति है, हम हर प्रकार से सहयोग

देने के लिए तैयार हूं लेकिन दूसरी ओर लोग दुखी है, उनके पास क्रय शक्ति नही है, उनके लिए खाद्यान्न और रोजगार की कोई व्यवस्था नही है। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान के नागरिक इस देश के नागरिक हैं, वहा की समस्या केवल राजस्थान की नही बल्कि पूरे देश की समस्या है। इन सारी बातो के निराकरण का पूरा दायित्व केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। यह कहना उचित नही होगा कि राजस्थान सरकार ने अपनी योजना बनाकर नही भेजी या दूसरी चीजे नही भेजीं। वहा के रहने वाले जो इस देश के नागरिक है वह भी जीना चाहते हैं आज उनके जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित है। वे आपसे माग करते है कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार से वे जुलाई अगस्त का महीना पकड सके।

सभापति महोदय मैं स्पीच अलाऊ नही करूंगा, आप प्रश्न कीजिए।

श्री वशेश्वर नाथ भार्गव मैं जानना चाहता हू कि वहा के मजदूरो को सरकार पर्याप्त मात्रा मे रोजगार देने की दृष्टि से क्या व्यवस्था कर रही है? आज वहा पर काफी इलाके ऐसे हैं जो मेरे जिले मे 976 गाव अकालग्रस्त हैं। पहला प्रश्न यह है कि वहा पर पर्याप्त मात्रा मे रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है दूसरे क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को उचित मात्रा मे धन राशि उपलब्ध करायेगी जिससे वहां पर रोजगार की व्यवस्था की जा सके? तीसरे ऐसे इलाको मे जहा निरतर अकाल की स्थिति रहती है जैसे अजमेर का बयावर इलाका है।

सभापति महोदय आप स्पीच मत दीजिए प्रश्न ही कीजिए।

श्री वशेश्वर नाथ भार्गव . किशनगढ तहसील निरतर अकालग्रस्त है। क्या आप वहां पर रोजगार की व्यवस्था करेंगे?

मैं यह भी मत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि जो खाद्यान्न आपने दिया है वह बहुत थोडा है उससे प्रति व्यक्ति तीन किलो भी नही आता है। इस लिए वहा पर खाद्यान्न की कमी को देखते हुए क्या उचित मात्रा मे गल्ला उपलब्ध किया जाएगा? 62 हजार आपने दिया है जो कि आवश्यकता से कम है। इस लिए क्या कम से कम 95 हजार टन इस महीने उपलब्ध कराएगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी मात्रा मे खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके जिससे वह कम से कम अपना जीवन यापन कर सके?

SHRI N K SANGHI (Jalore) Shri Shinde with his charming personality and sonorous vioce thinks that he can say something here and get away with it I am sure he will say the situation in Rajasthan is very grave The time I have is very short I would only like to say that people in Rajasthan are today feeling that the Central Government is complete y partisan in taking care of Rajasthan's problems

I would like to ask have you made any assessment of the famine condi tions in different States in the country, Rajasthan, Maharashtra, Mysore and Orissa etc, and as among them, can you tell us which State has more serious famine conditions, how many people are most affected in each State and what is the quantum of assistance you propose to give to the different States? You should have an independent assessment of the conditions in the various States Otherwise, we are bound to go away with the feeling that you are taking a partisan attitude in dealing with Rajasthan and Rajasthan is being neglected

In this context, I would like to say that Rajasthan has made a demand for assistance to the tune of Rs. 80 crores, but it has been given Rs. 6—7 crores. Maharashtra has demanded Rs. 180 crores and you have given it Rs. 94 crores. Is it suggested that the Rajasthan Government has made a Goebbles demand? The Rajasthan Government is not making bogus claims. (*Interruptions*) What is the outlook? What is your assessment?

I would also like to know whether it has come to your knowledge that the Manchanda Central Committee, when they went to Rajasthan—it has been reported—did not visit the affected areas? Lastely, for the time, when the Manchanda Committee went there, the Rajasthan Government refused to give them hospitality and made them wait in the Circuit House merely for the fact that they did not care to make proper assessments. I would like to have a clear-cut ideology

MR. CHAIRMAN: No, please. No speech

SHRI N. K. SANGHI: We are not saying that Maharashtra or any other State is getting this much and all that. What I would like to know is whether you are going to give grant-in-aid to the Railway Ministry so that some railway lines can also be constructed in Rajasthan? Today, as time passes, we are seeing what the Government is doing. The question is whether you will formulate any policy so that some subsistence is given from the Food and Agriculture Ministry by way of drought relief so that some railway line can also be given to Rajasthan. to suggest is, would you give some percentage of their outlay so that they may also be able to give some railway line and provide better employment and proper assistance. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I am not allowing anybody. Mr. Shinde.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Mr. Chairman, Sir, I am thankful to Mr. Daga, Shri Bhargava and Sanghi for raising this discussion. I am only sorry that some hon. Members have been feeling that the Centre is not being fair. Because of the difficult situation there and the pressure on them is very great that perhaps they may be justified in having some reservation in their mind. But I would just like to submit for their very humble consideration certain facts. But before I go into the facts, I would like to ask the hon. Members how the Centre can afford to be partisan or be partial in regard to one State or the other. (*Interruptions*). Please try to listen to me. After all, we are a federal set-up and we have certain mechanisms and certain procedures evolved. Even in regard to drought relief, we have certain sets of principles on the basis of which the Government of India operates. I have some very harsh questions to put. I would have avoided them but for the fact that some hon. Members have raised doubts about the Centre and some of them went to the extent of saying—Mr. Sanghi—that we are partisan. I am sorry, because I stand by my statement, because in a drought, human suffering is tremendous, and particularly in Rajasthan which is always a drought-prone area and the capacity to stand up against the natural calamities is very limited. So, I can imagine the suffering, and I stand by my earlier statement that whatever be the part of the country is equally dear to us—Rajasthan Maharashtra, Mysore or Gujarat, and the Government of India cannot have any other approach but be sympathetic to our brothers and sisters in all parts of the country including Rajasthan.

Now, the question has been raised why the Centre is given so much

limited assistance But I have to put some harsh questions If the Rajasthan Government is complaining perhaps some of their complaints is justified and I am not criticising the Rajasthan Government But out of the amounts which are available why are they not being spent? For instance, take the drought-prone areas programme 54 districts are selected in the country as a whole for building up permanent protection against drought The Largest number has been selected from Rajasthan 10 districts have been selected from Rajasthan alone The others have just two three or four-like that But the largest number is from Rajasthan Under that head Rs 20 crores for the Plan were available, and last year so far only Rs 8 14 crores have been spent up to December For this year itself Rs 7 14 crores were available The spending has been Rs 3 43 crores In fact, we even told the Rajasthan Government that even if they go beyond these limits because this is part of the Rs 20 crores scheme in the next year's budget, we are prepared to support them because they are sound schemes I do not know what are the difficulties of the Rajasthan Government We told them to go ahead with the expenditure on this head even beyond the budget limits Under this head we have given them We have made the finances available Then take the rash employment scheme Out of Rs 3 24 crores, which is the actual amount available only 2 54 crores have been spent The main point is that the Government of India is very much concerned not only in Rajasthan but all over the country that whenever we take up the drought relief operations, large amounts are spent on non-productive schemes Hon Members have been asking rightly why we should not take up the scheme, which would give permanent protection to drought affected people and drought affected areas? As a result of the drought, we do not want to expend money in non-productive schemes So whatever productive schemes there are, there will not be any limitation of funds, we shall give all the necessary funds

Mr Sanghi asked what are the schemes Take, for instance, Rajasthan canal According to our own assessment about one lakh of people can find employment in Rajasthan canal but only fifty thounsand persons are being employed We are asking them now that drought situation is there try to employ the maximum number of people that is possible (*Interruptions*)

If the budget goes beyond the provided amount, we shall support them My difficulty is that even in respect of such a useful project, the best project in the country which will solve some of the problems of those areas, but that project is not being completed I have no time to go into other details But during the last three or four years we have spent about Rs 100 crores on drought relief, while Rajasthan canal has been starving for lack of funds We have spent Rs 8 95 crores in 1968-69 Rs 51 18 crores in 1969 70 and Rs 32 00 crores in 1970-71 I wish the hon Members try to understand the position (*Interruptions*) I have already made a statement that if the Rajasthan Government takes up productive schemes for providing employment for drought relief, we shall finance and support them there will be no difficulty whether it is Rs 7 crores or 8 crores or 40 crores, nothing will come in the way Why should they doubt the *bona fides* of the Government of India in these matters My information is that on minor irrigation works about a lakh and fifty thousand people can be employed, whereas only 28 918 people are employed Take again soil conservation The Central Team's assessment is that about 1,500,000 people can work on this, where as only 16 000 people have been employed We shall support the Rajasthan Government, if they take up productive schemes

Afforestation is a very important scheme which will help the tribal people and the backward people there

According to the assessment of the Central Team, 50,000 persons can be employed on afforestation. Let them take up this productive scheme and we shall give them full support. In respect of non-productive schemes, I have this to say and I shall seek the co-operation and understanding of the hon. Members. Many times we construct roads in Rajasthan, but next year they disappear. Are we to go on spending like this? Is it in the interest of the country or of Rajasthan to do like this?

I hope the hon. Members will understand me and will appreciate the Government's approach in regard to this

In regard to drought, we have taken absolutely a new approach; whether it is Rajasthan or Gujarat or Maharashtra, we are going to tell them that if they are going to spend the funds on unproductive schemes, we will not support them. If it is a marginal case of non-productive expenditure I can understand that. There may be certain special circumstances to spend on non productive scheme. In Rajasthan, for example, we have noticed that 75 per cent of expenditure has gone only for roads which have disappeared. I have already spelt out my idea for the future Let the Rajasthan Government take up the schemes. We will support them.

Now, a word for Rajasthan Government lest I may be likely to be misunderstood. During the last few days it has been taking up very large relief works. They have taken up 2,136 relief works and about 6,45,000 people are working as against 75,000 who were working in relief works in December. Within the period of three months, the Rajasthan Government has taken steps to provide employment to a very large number of people.

18 hrs.

As far as food is concerned, I think we have made an allocation of 65,000 tonnes. I consider Rajasthan Government's requirement as very genuine 65,000 tonnes of food is a very substantial quantity. We had discussions with the State's representatives. Their demand is more. I think they should go a long way for meeting the requirements. The previous allocation was a little less. No doubt financial allocations have been made to meet the reasonable requirements of the Rajasthan Government. My senior colleague, Shri Fakaruddin Ali Ahmed has thoroughly gone into the requirements of the Rajasthan Government. It is only after this that we have arrived at some objective assessments. We shall continue to meet any reasonable requirements of the State I would request my hon. friends to bear with me that we have had enough or regionilism and we have had enough of provincialism. Let us always think that Rajasthan is part of the country We will never let down Rajasthan.

---

18 01 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Andhra Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd March, 1973".

18.1½ hrs.

ANDHRA PRADESH STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Andhra Pradesh State Legislature (Delegation of